

Irrigation project lies in neglect

It was built in Mulakapalli of Kothagudem district 45 years ago

JAMES EDWIN
KOTHAGUDEM

The Mukamamidi irrigation project, built 45 years ago, in Mulakalapalli mandal in the district, is crying for attention.

The project with a volume content of 160 million cubic feet is spread over 378 acres. This project is a rain-fed project and is meant to provide irrigation to farm fields in Kurupulagudem, Rangapuram, Mukamamidi, Mogaralagutta, Mulkalapalli, and others. The foundation stone for the dam was laid in 1978 by the then Chief Minister of erstwhile Andhra Pradesh Jalagam Vengala Rao. It was inaugurated in 1980 by the then Chief Minister Marri Chenna Reddy. About 3,260 acres could be cultivated through this project, whose source is Pamuleru Stream, a tributary of river Godavari. Officials said 15,570 cusecs of water would be discharged through the right and left canals of the project. However, the project later was left to its fate and is currently in a dilapidated state. As the project reached dead

SORRY STATE

- The rain-fed project has a volume content of **160 million** cubic feet and is spread **over 378 acres**
- The foundation stone was laid in **1978** by the then CM of erstwhile AP Jalagam Vengala Rao
- It was inaugurated in **1980** by the then Chief Minister Marri Chenna Reddy
- About **3,260 acres** could be cultivated through this project, whose source is Pamuleru, a tributary of river Godavari
- Officials said **15,570 cusecs** of water would be discharged through the right and left canals
- As the project reached dead storage level in summer, farmers stayed away from activity in Yasangi



“There are no signs of crops like paddy getting cultivated in the Vanakalam season either as the gates of the dam are in a damaged condition

— ARE RAMESH, Farmer

storage level in summer, local farmers stayed away from farm activity in the Yasangi season. There are no signs of crops like paddy getting cultivated in the Vanakalam season either as the gates of the dam are in a damaged condition, said a farmer Are Ramesh.

BJP district president Ranga Kiran, who visited the project recently at the request of the local farmers,

said the previous BRS government had sanctioned about Rs 9 crore in 2019 for the development of the project, and works worth Rs 6 crore had been completed. Speaking to Telangana Today, Kiran said the project gates were in a dilapidated condition because of which the water would flow out through these canals and the farmers could not get water when they needed it.

The dam weir was damaged in a couple of places and accumulation of silt reduced its storage capacity. According to irrigation officials the project needed Rs 21 crore for taking up repair works alone. The Congress government should release Rs 50 crore to carry out repairs, to remove the silt and develop it as a tourist spot as it is located in a forest area, the BJP leader said.

Rainfall likely to be below normal in June: IMD

Says overall precipitation for the month will also be subpar

NEW DELHI

India has received 20 per cent below normal rainfall since the start of the monsoon period on June 1, and overall precipitation for the entire month will also be subpar, the India Meteorological Department (IMD) has said.

After reaching the Indian mainland two days earlier than usual and swiftly covering many other States, the rain-bearing system made no significant progress between June 12 and 18, extending the wait for north India, which is reeling from a sweltering heat wave.

However, conditions are now favorable for further advancement of the monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh, northwest Bay of Bengal, Bihar and Jharkhand over the next three to four days, the weather department said.

India received 64.5 mm of rainfall between June 1 and 18 which is 20 per cent less than the long period average (LPA) of 80.6 mm, it said. Since June 1, northwest India has recorded 10.2 mm of rainfall (70 per cent less than normal), central India 50.5 mm (31 per cent less than normal), the south peninsula 106.6 mm (16 per

Heavy rain uproots trees in Srikakulam

SRIKAKULAM: Several trees were uprooted in the heavy rain, accompanied by gusty winds and thunderstorms, that lashed Ichchapuram in Srikakulam district and its neighbouring areas on Tuesday. Motorists had to temporarily seek shelter on the sides of the Tiruchi-Dindigul Highway.

Dozens of trees were uprooted due to the gusty winds causing damage to the parked vehicles and other properties. Electric poles also got uprooted causing disruption in power supply to many parts of the city, and neighbouring areas. ANI

cent more than normal), and east and northeast India 146.7 mm (15 per cent less than normal).

The southwest monsoon advanced into parts of the Nicobar Islands on May 19. It subsequently covered most parts of the south and some parts of central Bay of Bengal by May 26 along with Cyclone Remal. PTI

बाढ़ से संबंधित निर्माण कार्यों में भी नवाचार को दिया जा रहा है बढ़ावा: स्वतंत्र देव सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि लगातार नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर में प्रेशर सिंचाई प्रणाली विकसित किया जा रहा है, यह नई सिंचाई पद्धति है। प्रदेश में प्रथम बार प्रेशर सिंचाई प्रणाली का कार्य कराया जा रहा है।

स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रेशर सिंचाई प्रणाली में सेंट्रिफ्यूगल टैंक, पम्प हाउस तथा पीसीसी पाइप एवं डीआई पाइप का उपयोग किया जा रहा है। प्रेशर सिंचाई प्रणाली में पाइप (800 मिमी तथा 200 मिमी) लाइन जमीन से लगभग 1.5 मीटर नीचे बिछाया जा रहा है, जिससे कृषकों की जमीन पर खेती पूर्व की भांति होती रहेगी। इस सिंचाई प्रणाली में लगभग प्रत्येक 200 मीटर पर आउटलेट का प्राविधान है। पाइप में पानी का बहाव दबाव के होने के कारण ग्रेविटी फ्लो तथा पाइप



लगाकर कृषक अपने खेत की सिंचाई कर सकता है। यदि कृषक अपने खेत में स्प्रिंकलर प्रणाली विकसित कर रखा है तो उसे सिर्फ आउटलेट से अपने स्प्रिंकलर प्रणाली को जोड़ कर सिंचाई कर सकता है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रेशर सिंचाई प्रणाली की 07 नग परियोजना के अंतर्गत 11 स्थानों पर 31 किमी लम्बाई में पाइप लेईंग का कार्य प्रगति में है। 7 नग परियोजनाओं के द्वारा 57 ग्रामों के लगभग 18000 कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त परियोजना द्वारा खरीफ में 3969 हेक्टेयर तथा रबी में 3969 हेक्टेयर सिंचाई का प्राविधान है। 7 नग परियोजनाओं की लागत 111.62 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इसमें

निम्न प्रकार से नवीन प्राविधान किए गए। इसके तहत फैक्ट्री में डबायर क्रेट जिसके मेस की साइज 10 सेमी व 12 सेमी होती है जो छोटे बोल्टर पर भी प्रभावी रहता है। इसके तहत

डिजाइन में लांचिंग एग्रेसन के एग्रेसन की साइज विभाग में परम्परागत रूप से चल रहे 1 मी. गुण 1 मी. गुण 1 मी. के स्थान पर 1.5 मी. गुण 1.5 मी. गुण .5 मी का प्रयोग किया गया।

यह डिजाइन अधिक सुरक्षित व लागत में 25 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। इस डिजाइन को पूरे पूर्वी संगठन की बाढ़ परियोजनाओं में लागू कराया गया है।

प्रदेश में वर्षा जल के अधिकाधिक संचयन के लिए चल रहा 'कैच द रेन' अभियान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अधिकाधिक वर्षा जल संचयन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में चल रहा 'कैच द रेन' अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2019 से प्रतिवर्ष मार्च-अप्रैल से नवंबर तक चलने वाला ये अभियान इस वर्ष अपने पांचवें चरण में पहुंच चुका है। इसके अंतर्गत पारंपरिक जल निकायों, जलस्रोतों का नीवनीकरण और पुनः उपयोग, बोरवेल पुनर्भरण, वाटरशेड का विकास, गहन वनारोपण, छोटी नदियों के कायाकल्प के साथ ही नारी शक्ति से जल शक्ति के थीम पर जन जागरूकता कार्यक्रम, जिलों की हाइड्रो जियोलॉजिकल परिस्थिति

● छोटी नदियों के कायाकल्प से लेकर पारंपरिक जल निकायों और जलस्रोतों का हो रहा नीवनीकरण

के अनुसार जल संचयन संबंधी अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिलों के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय भवनों पर अनिवार्य रूप से रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कराने के निर्देश हैं। साथ ही यह भी निर्देश है कि जिलों के सभी अमृत सरोवरों के जल प्रवाह में रुकावट को ठीक किया जाए। 18 जून तक की रिपोर्ट के अनुसार जिलों के शासकीय और अर्द्धशासकीय भवनों पर अनिवार्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कराने के मामले में पीलीभीत,

अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और गोंडा क्रमशः टॉप फाइव में हैं। यहां शत प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं अमृत सरोवरों के रखरखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी क्रमशः टॉप फाइव जनपद हैं। यहां अमृत सरोवरों में सिल्ट और वनस्पतियों को साफ कराने का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही निर्माणाधीन अमृत सरोवरों के कार्य को भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने हाल ही में 'कैच द रेन अभियान 2024' की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया है कि यह केंद्र और योगी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।